



नरियात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)

हाल ही में केंद्र सरकार ने [नरियात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना \(TIES\)](#) पहल के तहत नरियात को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को 206 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

- TIES के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 27 नरियात बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है।

नरियात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES):

- **परिचय:**
 - केंद्रीय वाणज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में नरियात योजना (TIES) के लिये व्यापार बुनियादी ढाँचा शुरू किया।
 - वर्ष 2015 में नरियात और विकास के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार करने तथा सहायता (ASIDE) योजना से राज्यों के अलग होने के बाद राज्य सरकारें लगातार नरियात बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु केंद्र से समर्थन का अनुरोध कर रही थीं।
- **उद्देश्य:**
 - नरियात की वृद्धि के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना।
- **कार्य क्षेत्र:**
 - इस योजना का लाभ राज्यों द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण नरियात लिकेज जैसे- सीमा बाजार, भूमि, सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्द्धन केंद्र, नरियात वेयरहाउसिंग तथा पैकेजिंग, SEZ एवं बंदरगाहों/हवाई अड्डे, कार्गो टर्मिनल के साथ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये लिया जा सकता है।
- **वित्तीय सहायता की सीमा:**
 - बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होगी, आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना में यह कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी।
 - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों में स्थिति परियोजनाओं के मामले में (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ शासित प्रदेशों सहित) यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।
- **उन परियोजनाओं की नकारात्मक सूची जिन पर इस योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा:**
 - ऐसी परियोजनाएँ जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT जैसी क्षेत्र वशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।
 - सामान्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बजिली आदि।
 - सामान्य बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बजिली आदि।
 - ऐसी परियोजनाएँ जहाँ अत्यधिक नरियात लिकेज स्थापित नहीं किया जा सकता है।

TRADE INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS

Trade Infrastructure for Export Sector (TIES)

Department of Commerce was earlier working with states to fill infrastructure gaps through ASIDE.

As per 14th Finance Commission recommendations, tax devolution to states increased from 32% to 42%, thus delinking ASIDE from support of the Centre.

TIES launched to strengthen export infrastructure in March 2017.

Central Government funding normally not more than the equity put in by implementing agency or 50% of total project equity (80% for Northeastern & Himalayan states including J&K).



Scheme to help export-linked infrastructure projects like:

- o Border Haats
- o Land customs stations
- o Quality testing and certification labs
- o Cold chains
- o Trade Promotion centres
- o Dry Ports
- o Export warehousing and packaging
- o SEZs and ports/airports cargo terminuses

//

स्रोत:पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/trade-infrastructure-for-export-scheme-ties-scheme->

